

भारत सरकार  
ग्रामीण विकास मंत्रालय  
ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा  
अतारांकित प्रश्न सं. 4069  
(25 मार्च, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए)

ग्रामीण क्षेत्रों का विकास

4069. श्री दर्शन सिंह चौधरी:

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार की ग्रामीण क्षेत्रों के समग्र विकास के लिए योजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ख) सरकार द्वारा गरीबी मुक्त भारत के लिए गरीबी मुक्त गांवों का संकल्प पूरा करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर  
ग्रामीण विकास राज्य मंत्री  
(श्री कमलेश पासवान)

(क) से (ख): ग्रामीण विकास मंत्रालय देश के ग्रामीण क्षेत्रों के समग्र विकास के लिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा योजना), प्रधानमंत्री आवास योजना -ग्रामीण (पीएमएवाईजी), प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई), दीनदयाल अंत्योदय योजना -राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीआई-एनआरएलएम), दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयूजीकेवाई), ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरएसईटीआई) और राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी), प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई) का वाटरशेड विकास घटक (डब्ल्यूडीसी) जैसी अनेक कल्याणकारी योजनाएं/कार्यक्रम कार्यान्वित कर रहा है। इन योजनाओं/कार्यक्रमों का उद्देश्य गरीबी उपशमन करना तथा आजीविका के अवसरों में वृद्धि करके, न्यूनतम गारंटीकृत रोजगार उपलब्ध कराकर, स्वरोजगार को बढ़ावा देकर, विभिन्न उपयोगी व्यवसायों एवं उद्यमिता गुणों में युवाओं का कौशल विकास करके, अवसंरचना विकास तथा सामाजिक सहायता के प्रावधान द्वारा देश के ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के जीवन की गुणवत्ता में समग्र सुधार लाना है।

इसके अलावा, वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट में, सरकार ने एक व्यापक बहुक्षेत्रीय 'ग्रामीण समृद्धि और अनुकूलन' कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा की है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य कौशल, निवेश, प्रौद्योगिकी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाकर कृषि में अल्प बेरोजगारी का समाधान करना है। ग्रामीण क्षेत्रों में पर्याप्त अवसर पैदा करने के उद्देश्य से ग्रामीण महिलाओं, युवा किसानों, ग्रामीण युवाओं, सीमांत और छोटे किसानों तथा भूमिहीन परिवारों पर सर्वाधिक ध्यान दिया जाएगा।

\*\*\*\*\*